लेकिन आपके शब्दों पर जहां तक विश्वास करने की बात है आपके शब्दों पर कम से कम मैं विश्वास नहीं कर सकता ।

प्रधान मंत्री जी यहां आकर कहते या वित्त मंत्री यहां आकर कहते, तो मैं विश्वास कर लेता । लेकिन अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आपके शब्दों पर भी शक नहीं करेंगे, विश्वास नहीं होता और कारण है कि आज भी बहुत से वर्कर्ज निकाले जा रहे हैं और इनमें से किसी को भी आज तक आपने ट्रेनिंग भेजा नहीं है । अगर आप आज भी कहते कि इनको ट्रेनिंग भेजो, मान लूंगा । महोदया, एक आपसे भी शिकायत करनी है । कम से कम मेरी पार्टी की तरफ से जो कालिंग अटेंशन दिया गया था वह फाइनांस मिनिस्टर को दिया गया था और उसमें था

fairly to provide sufficient funds etc

वह बदल दिया गया । मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या दिया लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, उन्हें भी दिया था, तो यदि फाइनांस मिनिस्टर के साथ में यह होता तो शायद हमको संतोषजनक उत्तर मिल सकता था । डा. मनमोहन सिंह जी मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वित्त मंत्री हैं, उनसे कुछ समझ में आ सकता था । लेकिन अफसोस यह है कि बेचारी एक बहन को खड़ा कर दिया गया है । शायद प्रधान मंत्री जवाब देना नहीं चाहते थे । वित्त मंत्री जी की भी हिम्मत नहीं थी । उन्होंने कहा कि घड़ा किसी और के मत्थे फोड़ दो । तो इस बेचारी सीधी-सादी महिला के मत्थे फोड़ दिया गया है, जो कि उचित नहीं है । लेकिन मैं समझता हूं कि वाक आउट किए बिना मैं भी अपने दल की ओर से पूरे जोर के साथ अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करना चाहता हूं ।

उपसभापति : ऐसा है कि कालिंग अटेंशन चेयरमैन साहब ने एडमिट किया, सरकार को भेजा । सरकार जो मुनासिब समझती है जिस मंत्रालय से उसको जवाब देना चाहिए सरकार ने वह मंत्रालय को दिया । यह हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं चेयर डिसाइड नहीं करती है कि कौन-सा मंत्री जवाब देगा । ...(**व्यवधान**)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : हमने जो कालिंग अटेंशन दिया है why you have changed it.

उपसभापति : चेंज नहीं हुआ, पब्लिक सेक्टर का था इसलिए पब्लिक सेक्टर को चला गया ।

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Madam, I wish to mention only one point. I will take half-a-minute. See, in economics we have learnt there are five factors *of* production------------ man, money, machines, land and materials. Even if you gave them all or make them available, there was one thing, the most important element which was missing in ihe Governmental activity and that was professional management. That professional management was not available to these public sector undertakings and this is one of the factors responsible for failure and sickness because most of the companies were managed by IAS officers: they were not professionally trained They were not tuned. They had no attitude They had never seen the face of a labourer or machine or anything related to it. So I construe that it was a major blunder on the part of the Government not to have professionals to manage these public sector undertakings, and huge funds were lost.

Everything will be lost unless you have professional management in these public sector undertakings. Thank you

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now we will take up the Statutory Resolution and the Jammu and Kashmir Appropriation (No. 2) Bill. 1993 for consideration. Before that, we have two messages from the Lok Sabha.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

(I) The Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1993.

(II) The Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1993.

SECRETARY-GENE RAI.: Madam. I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :—

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 *of* the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. I am directed to enclose the Appropriation (Railways) No. 3 Bill. 1993, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 25th August. 1993.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

(II)

"In accordance with the provisions *of* rule % of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed *to* enclose the Appropriation (Railways) No. 4 Bill, 1993, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 25th August, 1993.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Madam, I lay a copy of each of the Bills on the Table.

उपसभापति : श्री कृष्ण लाल शर्मा । शर्मा जी, हम लोग साढे चार बजे शुरू कर रहे हैं और तीन घंटे दिए हैं । वैसे तो आपकी पार्टी के 23 मिनट हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात संक्षेप में कह सकें यही बातों को तब हाउस आपका आभारी होगा ।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : कुल कितना टाइम है ?

उपसभापति : तीन घंटे हैं । उसमें दो मंत्रियों का भाषण भी शामिल है । दो मंत्रियों का तो 3 घंटे में से एक घंटा तो चला गया । इस प्रकार दो घंटे ही बचे । ....(**व्यवधान**) No; we have got so much business. अभी रेलवे का आ गया है । कल का दिन अकेला रह गया है । तो किसी भी हालत में आज ही इसको खत्म करना है ।

I. STATUTORY RESOLUTION SKKK1NG APPROVAL OF THE CONTINUANCE IN FORCE OF PRESIDENT'S PROCUMATION IN RELATION TO THE STATE OF JAMMU AND KASHMIR

II. THE JAMMU AND KASHMIR APPROPRIATION (NO. 2) BILL, *1993-Contd*

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति महोदया, इस समय जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1993 और जो राष्ट्रपति द्वारा धारा 356 के अंतर्गत 18 जुलाई, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा थी उसे 31 सितम्बर के बाद 6 महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन जम्मू-कश्मीर में बढ़ाने के लिए यह दोनों विषय संयुक्त चर्चा के लिए इस समय सदन में प्रस्तुत है ।

मैं पहले जम्मू-काश्मीर विनियोग विधेयक के संबंध में कुछ बातें कहूंगा महोदया, हमारे इस विनियोग विधेयक में जो बातें जम्मू-काश्मीर के संबंध में कही गयी हैं, इसमें एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि यह जो करोड़ो रुपए हम खर्च कर रहे है जम्मू-काश्मीर पर, वह कहां जा रहा है ? अगर संबंधित मंत्री महोदय कोई परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बता दें तो ठीक रहेगा कि पहले जो हमने धनदान दिए वह कहां खर्च हुए और वह खर्च हुए तो संतुलित रूप से खर्च हुए, विकास कार्यों में खर्च हुए या कहीं और चले गए क्योंकि इससे कोई स्पष्ट बात सामने नहीं आती है । महोदया, जम्मू-काश्मीर का मामला वित्त के सम्बन्ध में ऐसा हो गया है कि शायद यह डिवीजन ऑफ लेबर है कि जितनी रेवेन्यू है, जितनी इनकम है वह तो जम्मू और लद्दाख रीजन से प्राप्त होती है और जितना खर्चा होता है, वह काश्मीर वैली पर होता है । मैं वित्त मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह अगर इस बात को स्पष्ट करें कि पिछले तीन वर्षों में या कम से कम इस वर्ष में हमें जम्मू-काश्मीर के पूरे प्रदेश का नहीं तो केवल काश्मीर वैली में से कितना रेविन्यू प्राप्त हुआ और किस-किस मद में प्राप्त हुआ ? हमारी जानकारी के हिसाब से तो न कोई वहां बिजली का बिल देता है, न दूसरे विषयों के लिए बिल देता है । वहां पर कोई भी नियम लागू ही नहीं है, कोई टैक्स या किसी प्रकार की और चीज घाटी पर अगर लागू है, तो इस बारे में आप जानकारी दें । फिर मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सारे विनियोग विधेयक में इस समय जो जम्मू-काश्मीर की बहुत बड़ी समस्या है विस्थापितों की, इसमें कोई पैसा उसके लिए रखा नहीं गया है । अगर रखा गया है तो वित्त मंत्री महोदय मुझे बताएं । करीब ढाई लाख विस्थापित वहां से निकाले गए हैं जोकि जम्मू में हैं, बाहर भी हैं और उसके लिए इस विनियोग विधेयक में कोई पैसा ही न हो, यह एक आश्चर्य की बात है । दूसरी बात, पर्यटन के लिए पैसा रखा गया है । मैं जानना चाहता हूं कि पर्यटन का पैसा कहां खर्च हो रहा है ? मेरी जानकारी के हिसाब से तो कोई पर्यटन की एक्टिविटी या सक्रियता काश्मीर घाटी में इस समय नहीं है और जहां पर्यटन की कोई एक्टिविटी है वहां उनको सहायता नहीं है । महोदया, इस समय जम्मू-काश्मीर में सबसे बड़ा अगर पर्यटन का कोई स्थल है तो वह वैष्णो देवी की यात्रा है । जम्मू से दिल्ली और दिल्ली से जम्मू के लिए कोई हवाई जहाज प्रोवाइड हम नहीं दे रहे हैं । इसके अलावा भी पर्यटकों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए, उस दृष्टि से कुछ सोचा नहीं जा रहा है । एजुकेशन और अनेक जरूरी मुद्दों पर भी कोई खर्च नहीं हो रहा है । मेरा यह निवेदन है कि जम्मू-काश्मीर की समस्या का समाधान इसमें है कि पहली बात जो भी पैसा लेते हैं वह तीनों क्षेत्रों—काश्मीर घाटी, जम्मू क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र, इनके लिए अलग-अलग पैसा विकास-

(उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) पीठासीन हुए)

कार्यों के लिए दिया जाए और इस बारे में परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाए कि वह अलग-अलग कार्यों पर कहां-कहां खर्च हुआ और कहां-कहां उसका उपयोग हुआ ? नहीं तो आज ऐसी स्थिति बन गयी है कि जहां हम घाटी में पैसा लगा रहे हैं वह तो नष्ट हो रहा है । यहीं तक नहीं, वह पैसा आतंकवादियों के पास जा रहा है । विकास के नाम का पैसा आतंकवादियों के पास पहुंच रहा है जिससे कि वे शस्त्र ला रहे हैं और भारत के खिलाफ उनका उपयोग हो रहा है और जहां जम्मू में, लद्दाख में जो पैसा खर्च होना चाहिए वह हम खर्च नहीं कर रहे हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि विस्थापितों के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए । पर्यटन के लिए जो पैसा है, वह जम्मू क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में भी खर्च होना चाहिए और कुल मिलाकर तीनों क्षेत्रों के संतुलित विकास की योजना बननी चाहिए और उसके लिए पैसा दिया जाना चाहिए अन्यथा यह विनियोग विधेयक पक्षपातपूर्ण माना जाएगा ।

एक बात और कहना चाहता हूं । आप यह छह महीने के लिए और राष्ट्रपति शासन बढ़ा रहे हैं । चव्हाण साहब यहां उपस्थित हैं । गृह मंत्रालय में भी शायद काम बंटा हुआ है । स्थिति सुधरी है और चुनाव कराने के लिए वातावरण अनुकूल है, यह वक्तव्य अगर देना होगा तो दूसरे मंत्री आएंगे । वह आज नहीं है यहां । आज चव्हाण साहब कह रहे हैं कि वहां परिस्थिति